"Public order" which is a State subject, according to Schedule VII of the Constitution of India. Substantive action under the law in such cases has to be taken by the State/UT Governments concerned. However, the Centre keeps in close touch with the State Governments and offers suggestions to them from time to time to expedite measures aimed at removing the basic factors responsible for such incidents and for strengthening the administra-

tive machinery to ensure prompt and effective action in such cases and to provide protection to and instil a sense of security among the weaker sections.

According to the information furnished by the State Governments till dated, the following are number of cases of crimes against members of Scheduled Castes reported in the States of Bihar, Maharashtra and Andhra Pradesh during 1976 and 1977:

State						1976	1977	
Bihar .		•	•		•	621	421	(Upto October)
Maharashtra		•	•	•		211	367	(Upto September)
Andhra Pradesh	•	•	•	•	•	34	70	(Upto September)

## मध्य प्रदेश के गांव में सड़कों का विकास

358. श्री म्राधन सिंह ठाकुर : क्या नौयहन ग्रीर परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विया यह सच है कि मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बस्तर जिले में 90 प्रतिशत गांवों के विकास के लिए पहुंच सड़कों की बहुत स्नावश्यकता है; स्रोर
  - (ख) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता से वहां पहुंच सड़क बनाने के लिए कोई योजना बनायेगी?
- नौबहन ग्रोर परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम ): (क) ग्रोर (ख). गांवों का विकास ग्रोर उनमें पहुंच-सड़कों का निर्माण राज्य का विषय है। इसलिए, यह मध्य प्रदेश सरकार का काम है कि वह ग्रावश्यकता का मूल्यांकन करे ग्रोर संबंधित पहुंच-सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यंक्रम की योजना बनाए। परन्तु इस मामले में उनसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुन्ना है।

1977-78 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में योजक सड़क बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 170 लाख रु० की राशि दी गयी। इसके ग्रालावा, योजना ग्रायोग ने भी 1977-78 में जनजाति उप-योजना के ग्रन्त-गंत मध्य प्रदेश में सम्पूर्ण जनजाति उप-योजना के लिए 'परिवहन ग्रोर संचार' के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य की योजना ग्रोर प्रावधान में से उन्हें 440 लाख रु० दिए।

## बस्तर जिले में टेलीविजन फेन्द्र

- 359. श्री श्रथन सिंह ठाकुर: क्या सूचना श्रीर प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर टेलीविजन केन्द्र हैं;
- (ख) क्या सरकार का विचार लोगों को शिक्षित करने के लिए बस्तर जिले में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का है ; श्रौर
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं भ्रीर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यीरा क्या है?